विचार बिन्दु

तृण से हल्की रूई होती है और रूई से भी हल्का याचक। हवा इस डर से उसे नहीं उड़ाती कि कहीं उससे भी कुछ न माँग ले। –चाणक्य

राजस्थान : महात्मा गांधी स्कूल ये क्या हाल हो गया!

राजस्थान, भारत का वह राज्य जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, आज शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। विशेष रूप से, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जो कभी अभिभावकों और छात्रों की पहली पसंद हुआ करते थे, आज शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण अपनी चमक खो रहे हैं। शिक्षा विभाग के आंकडे और हाल के प्रयास इस स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। महात्मा गांधी स्कूलों की प्रारंभिक लोकप्रियता काफी थी ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू किए गए थे। इन स्कूलों का उद्देश्य था कि निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार, जो निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन नहीं कर सकते, अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर सकें। इन स्कूलों की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, और प्रारंभ में इनका आकर्षण इतना था कि प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाता था। इन स्कूलों ने न केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का वादा किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह शिक्षा मुफ्त या बहुत कम लागत पर उपलब्ध हो। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अभिभावकों में इन स्कूलों के प्रति भारी उत्साह देखा गया। लेकिन सरकार बदली और उपेक्षित इन स्कूलों की लोकप्रियता में कमी आती चली गई। सबसे पहले तो राज्य की भाजपा सरकार का असमंजस पूर्ण रवैया ही इसके पीछे कारण रहा। सरकार ने पहले तो यह ऐलान कर दिया कि सरकार इन महात्मा गांधी स्कूलों को बन्द करेगी। फिर बहुत मंथन, दबाव और मांग के बाद सरकार ने आधे-अधूरे मन से इनके जारी रखने का ऐलान तो कर दिया लेकिन सरकार ने इन्हे उपेक्षित अवश्य छोड़ दिया। जिनमें सबसे प्रमुख है शिक्षकों की कमी और शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट। शिक्षकों की कमी यह एक गंभीर संकट है इन स्कूलों का। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आंकडों के अनुसार, महात्मा गांधी स्कूलों में कुछ अर्से पहले 23,000 शिक्षकों के पद रिक्त थे। सरकार ने हाल ही में 3,737 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की, लेकिन इसके बावजूद 11,424 पद अभी भी खाली हैं। यह आंकडा अपने आप में इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। खास बात यह है कि इनमें से कई स्कूलों में प्रिंसिपल तक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आश्चर्यजनक है कि केवल इन में से केवल 380 स्कूलों को ही नए प्रिंसिपल मिल पाए हैं। जहां स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसी होगी अनुमान लगाया जा सकता है। ऊपर से शिक्षकों की कमी का प्रभाव स्कूलों की कार्यप्रणाली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिना पर्याप्त शिक्षकों के, कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं, जाहिर है जिसके कारण पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में स्कूलों का प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर पड़ा हुआ है, जिससे अनुशासन और शैक्षिणक गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है।

महात्मा गांधी स्कूलों की लोकप्रियता में कमी का एक प्रमुख कारण इनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट है। जहां पहले इन स्कूलों में प्रवेश के लिए लंबी कतारें लगती थीं, वहीं अब स्थिति यह है कि कई स्कूलों में उपलब्ध सीटों से भी कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि कई स्कूलों में तो सीटें खाली रह गईं, और अब 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। इस गिरावट के पीछे कई कारक हैं। पहला, शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं प्रभावी ढंग से नहीं चल पा रही हैं। दूसरा, बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, और खेल के मैदानों की कमी ने भी अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। तीसरा, निजी स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों में शिक्षण का स्तर और संसाधन अब उतने प्रतिस्पर्धी नहीं रहे। नतीजतन, अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़े। महात्मा गांधी स्कूलों की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। ग्रामीण स्कूलों में न केवल शिक्षकों की कमी है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शौचालय, पीने का पानी, और उचित भवन तक की कमी है। कई स्कूलों में कक्षाएं खुले में या जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल रही हैं। पिछले साल आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्त किया गया। इससे हिन्दी माध्यम स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी हो गई, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह स्थिति ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि उनके पास निजी स्कूलों का विकल्प भी नहीं होता। ट्रांसफर और पोस्टिंग का प्रभावशिक्षा विभाग ने हाल ही में कई शिक्षकों को उनके गृह जिलों में स्थानांतरित किया है। हालांकि यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इससे स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। समय रहते संतुलित ढंग से योजना लागू करना शिक्षा विभाग कब का भूल चुका है। कई स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण वहां शिक्षकविहीन स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा, अंग्रेजी माध्यम में कार्यरत शिक्षकों को भी अन्य स्कूलों में भेजा गया, जिससे महात्मा गांधी स्कूलों की स्थिति और भी खराब हो गई। यह ट्रांसफर नीति न केवल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, बल्कि हिन्दी माध्यम स्कूलों पर भी भारी पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी थी। इस तरह की नीतियों से शिक्षा व्यवस्था का संतुलन बिगड़ गया है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है। आधे-अधूरे प्रयासों से क्या है समाधान निकलेगा सोच सकते हैं? राज्य सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। हालांकि, यह प्रयास भी आधा-अधूरा ही नजर आता है। अभी भी हजारों पद खाली हैं, और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा, शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं तेजी से भर्ती प्रक्रिया अपनाकर। सरकार को खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को और तेज करना होगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकों का प्रशिक्षण सशक्त बनाना जरूरी है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक है। कई शिक्षक, जो पहले हिन्दी माध्यम में पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी माध्यम में प्रभावी ढंग से पढ़ाने में असमर्थ हैं। स्कूलों मैं बुनियादी सुविधाओं के विकास की बुनियाद बहुत कमजोर है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि कक्षा कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, और पुस्तकालय का विकास में बहुत पिछड़े हैं ये स्कूल। समुचित व्यवस्था न केवल छात्रों को आकर्षित करेगी, बल्कि शिक्षकों के लिए भी कार्यस्थल को बेहतर बनाएंगी। शिक्षकों के स्थानांतरण में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को न बढ़ाएं। स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता और संसाधनों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखनी होगी। इसके लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है। अभिभावकों और छात्रों में महात्मा गांधी स्कूलों के प्रति विश्वास बहाल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। वस्तुतः महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान सरकार की एक दूरदर्शी योजना थी, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास किया। हालांकि, शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, और गलत नीतियों के कारण इन स्कूलों की स्थिति आज चिंताजनक है। यदि सरकार इस दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम नहीं उठाती, तो ये स्कूल अपनी पहचान और उद्देश्य दोनों खो सकते हैं। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, और इसे मजबूत करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी स्कूलों को फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए न केवल शिक्षकों की भर्ती, बल्कि समग्र शैक्षिक सुधारों की जरूरत है। यह समय है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस दिशा में गंभीरता से काम करें, ताकि राजस्थान के छात्रों को वह शिक्षा मिल सके, जिसके वे हकदार हैं।

वस्तुतः महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान सरकार की एक दूरदर्शी योजना थी, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास किया। हालांकि, शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, और गलत नीतियों के कारण इन स्कूलों की स्थिति आज चिंताजनक है। यदि सरकार इस दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम नहीं उठाती, तो ये स्कूल अपनी पहचान और उद्देश्य दोनों खो सकते हैं। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, और इसे मजबूत करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

संवेदना बनी सहारा : अंत्योदय शिविर ने असहाय महिला को संबल दिया

ग्राम पंचायत मानसागर के बावड़ी में अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर के प्रभारी रामदयाल सोमरौड़ के सामने एक मामला आया

- शिविर प्रभारी दिव्यांग महिला के घर पहुंचे, वहां सरपंच, परिजनों व अन्य ग्रामवासियों से स्थिति समझी
- दिव्यांगता पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में परिवर्तित कर मौके पर ही पेंशन पुनः चालू की गई

शासन और प्रशासन आमजन की सेवा के लिए हैं, लेकिन जब तक इनकी एप्रोच में करूणा, आपसी समझ और व्यक्ति, स्थान, समुदाय विशेष की आवश्यकता के मुताबिक सेवा शामिल नहीं हो, सुशासन का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की इसी भावना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कर रही है और जुलाई माह के पहले दिन जोधपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जो ऐसे अभियानों की सफलता के लिए के लिए एक केस स्टडी है।

इस दिन ग्राम पंचायत मानसागर के बावड़ी में कुछ असाधारण घटा। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर के प्रभारी रामदयाल सोमरौड़ के सामने एक चुनौतीपूर्ण मामला आया। एक ऐसी महिला, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसकी दिव्यांगता पेंशन बंद हो चुकी थी और आधाार कार्ड भी जारी नहीं हो पा रहा था। उसके पास आधार के साथ ही जनाधार या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज़ भी नहीं था। शिविर प्रभारी ने इस समस्या को चुनौती के रूप में लेते हुए इसका करूणा और संवेदना से समाधान कर अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को राज्य और समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का राज्य सरकार का संकल्प पूर्ण किया। शिविर प्रभारी दिव्यांग महिला के घर पहुंचे, वहां सरपंच, परिजनों व अन्य ग्रामवासियों से स्थिति समझी। दस्तावेज़ों के अभाव में भी उन्होंने शिविर में मौजूद विभागीय अधिकारियों से सहयोग लेकर आवश्यक प्रमाण जुटाए। यह पुष्टि हुई कि महिला की आयु 1 जनवरी, 2025 को 55 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। इस आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दिव्यांगता पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में परिवर्तित कर मौके पर ही पेंशन पुनः चालू कर दी गई। महिला खुद तो शायद उस राहत की गहराई न समझ सकी, लेकिन उसके परिवार, गांव के लोग और सरपंच ने इस छोटे-से बड़े कदम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक पेंशन नहीं, एक असहाय को उसकी पहचान, गरिमा, अधिकार लौटाना है। यह कहानी एक उदाहरण बन गई-जब संवेदना व्यवस्था से मिलती है, तो कोई भी सहायता अधूरी नहीं रहती।

आकांक्षा पालावत
उप निदेशक, जोधपुर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय।

प्रशासन में सचिवों का बार-बार तबादला

अशोक कुमार

"प्रशासन में सचिवों का बार-बार तबादला" एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बहस होती रहती है, खासकर जब इसका असर नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर पड़ता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

प्रशासनिक स्थिरता का महत्व

यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी नीति को सफल बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब शीर्ष अधिकारी, जैसे कि सचिव, बार-बार बदलते हैं, तो हर नए व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएँ और कार्यशैली होती है। इससे पिछली योजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया जा सकता है, या उनमें लगातार बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कोई भी नीति कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाती।

प्रभाव–

संस्थागत स्मृति का नुकसान: लगातार तबादलों से विभाग की संस्थागत स्मृति कमजोर होती है। नए अधिकारी को पिछली सफलताओं और विफलताओं को समझने में समय लगता है।

विश्वास और समन्वय में कमी: नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों (मंत्रालयों, विशेषज्ञों, ज़मीनी कार्यकर्ताओं) के साथ समन्वय ज़रूरी होता है। जब नेतृत्व लगातार बदलता है, तो इन संबंधों को स्थापित करने और विश्वास बनाने में बाधा आती है।

कार्यान्वयन में बाधा: नीतियों को ज़मीन पर उतारने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। नेतृत्व बदलने से कार्यान्वयन की गति और दिशा प्रभावित हो सकती है।

जवाबदेही का निर्धारण मुश्किल: जब कोई अधिकारी लंबे समय तक एक परियोजना का हिस्सा नहीं रहता, तो उसकी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

समाधान की आवश्यकता–

सरकार अक्सर प्रशासनिक दक्षता और लचीलेपन के नाम पर तबादलों को ज़रूरी मानती है। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि स्थिरता और निरंतरता के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए। इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक बदलावों से नहीं, बल्कि व्यापक नीतिगत सुधारों से हो सकता है। इसमें अधिकारियों के कार्यकाल को एक निश्चित अवधि के लिए तय करना और उन्हें पर्याप्त समय देना शामिल हो सकता है ताकि वे अपने विभागों में सुधार ला सकें और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकें।

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक निर्णय देश के विकास और नीतिगत लक्ष्यों में बाधा न बनें। सरकार प्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे पर कोई ठोस नीतिगत बयान नहीं देती है, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर शिक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं द्वारा लगातार बहस की जाती है।

स्थिरता निश्चित रूप से एक अच्छी नीति के निर्माण और सफल कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सरकार को प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्थिरता के बीच एक संतुलन खोजने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा क्षेत्र को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। यह संभव है कि सरकार आंतरिक रूप से इस पर विचार करती हो, लेकिन प्रशासनिक दक्षता और लचीलेपन को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती हो।

स्थिरता के बिना एक सुदृढ़ नीति का निर्माण और उसे सफलतापूर्वक लागू करना लगभग असंभव है। यह सिर्फ शिक्षा नीति पर ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र की नीति पर लागू होता है। संक्षेप में, स्थिरता केवल नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए ही नहीं, बल्कि उसके कुशल और प्रभावी निर्माण के लिए भी एक पूर्व शर्त है। जब तक शीर्ष पदों पर पर्याप्त स्थिरता नहीं होगी, तब तक न तो दूरगामी और प्रभावी नीतियां बन पाएंगी और न ही उन्हें जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा जा सकेगा। सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वास्तविक और स्थायी सुधार लाए जा सकें। क्या आप मानते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक बदलावों से हो सकता है, या इसके लिए व्यापक नीतिगत सुधारों की भी आवश्यकता है?

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

प्रवासी दृष्टि : समाज, संस्कृति और सोच दुबई की रोशनी में छिपी परछाइयां

डॉ. पंकज राजवंशी

विश्व कप के फाइनल के बाद का वो दृश्य, विराट कोहली का अनुष्का को गले लगाना, पूरे भारत के लिए एक भावनात्मक लम्हा था। एक विजेता की खुशी, एक जीवनसाथी का गर्व, और उस सबके बीच एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखा व्यक्तिगत प्यार का एक पल। मगर हम जैसे लोगों के लिए, जो तीस साल से अमेरिका जैसे खुले समाज में रहते हैं, जहाँ स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन सामान्य बात है, उस दृश्य में एक और परत थी। वो सवाल

जो मन में आया: क्या ये दुबई में क़ानूनी रूप से स्वीकार्य था? असलियत ये है कि विराट और अनुष्का इतने विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि शायद उन्होंने इस बारे में सोचा तक नहीं होगा। उनकी सेलिब्रिटी पहचान उन्हें एक ऐसी अदृश्य छूट देती है जो आम व्यक्ति को नहीं मिलती, ख़ासतौर पर उस पर्यटक या मज़दूर को जो गरीब है, सांवला है, और बेआवाज़ है।

दुबई, जो खुद को दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक शहरों में गिनाता है, वहाँ सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन, चाहे वो गले मिलना ही क्यों न हो, कभी-कभी नियमों की सीमाओं को पार कर सकता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, हल्के स्तर का स्नेह, जैसे हाथ पकड़ना या हल्का गले मिलना, आम तौर पर सहन कर लिया जाता है। लेकिन चुंबन या ज़्यादा अंतरंगता सार्वजनिक जगहों पर जुर्माने या गिरफ़्तारी तक का कारण बन सकती है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आपको कौन देख रहा है, और आप किस 'स्तर' से आते हैं। मेरी पत्नी, मैं और बच्चे हाल ही में दुबई गए थे। हम अमेरिकी नागरिक होने के नाते वहाँ पर्यटक की तरह गए थे। कई देशों में प्रवासी मज़दूर देखे हैं, लेकिन दुबई का अनुभव कुछ अलग था, थोड़ा असहज करने वाला। पूरा शहर एक शानदार, चमचमाता होटल लग रहा था। हर चीज़ सुव्यवस्थित, चमकदार, महँगी, लेकिन हर मुस्कराहट के पीछे एक डर छिपा हुआ।

जो टैक्सी चला रहा था, जो होटल की सफाई कर रहा था, जो रेस्तरां में खाना परोस रहा था, उनमें अधिकांश भारतीय या दक्षिण एशियाई थे। और हर किसी की आँखों में एक बात साफ थी: हम यहाँ आज़ाद नहीं हैं, पर हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। अचानक कुछ चेहरे याद आए। तीस साल पहले, अमेरिका आने से पहले, मैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक मेडिकल सेंटर में काम करता था जहाँ इन मज़दूरों के वीज़ा के लिए सिर्फ़ फिजिकल चेकअप होते थे। लंबी लाइनें होती थीं, भीड़ जैसे चलतीं, भेड़-बकरियों की तरह, एक के बाद एक। उन चेहरों को इन चेहरों से तुलना करूँ तो क्या सही और क्या ग़लत? मैं उनकी आज़ादी न होने से विचलित हुआ, अन्याय से या अपने पूर्वग्रहों से?

यूएई की 'कफ़ाला प्रणाली' के तहत विदेशी कामगार अपने नियोक्ताओं पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। पासपोर्ट नियोक्ता के पास, नौकरी बदलने के लिए उसकी इजाज़त ज़रूरी, देश छोड़ने के लिए भी वही मर्जी का मालिक। अब आप सोचिए, किसी भारतीय मज़दूर को जब भारत में 10-12 हज़ार रुपए महीना मिलते हैं, और दुबई में उसे 1200-1500 दिरहम यानी 27,000-35,000, तो वो क्या करेगा? यहीं आ जाएगा, फिर चाहे इंसानियत कहीं खो जाए। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर जो तंत्र दुबई ने तैयार किया है, वह बहुत हद तक एक भारतीय घर के मॉडल पर आधारित है, जहाँ घरेलू सहायिका 'घर का हिस्सा' कहलाती है, पर उसे कभी समानता नहीं मिलती। दुबई में यह मॉडल औद्योगिक स्तर पर है। हर टॉवर, होटल, मॉल, एयरपोर्ट किसी विशाल भारतीय घर की तरह है, जहाँ सारे काम करने वाले प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हैं, बेहतर जीवन की उम्मीद में।

पर वो बेहतर जीवन कैसा है? एक रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण स्थल पर काम करने वाले मज़दूरों को 45 से ज़्यादा गर्मी में भी दिन के 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। सस्ते डॉरमेट्री टाइप कैंपों में 6-8 लोग एक कमरे में रहते हैं। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, वो भी अगर नियोक्ता दयालु हो। और अगर कोई विरोध करे या शिकायत करे? पासपोर्ट जब्त, वीजा रद्द, पुलिस बुला लो, डिपोर्ट कर दो।

अब ज़रा सोचिए, दुबई खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कहता है। हर कोने में कैमरा, हर व्यक्ति पर नज़र, हर व्यवहार पर नियंत्रण। लेकिन ये सुरक्षा किसके लिए है? विदेशी निवेशक, पर्यटक, या अमीर रेज़िडेंट्स के लिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए? उनके लिए यह एक सुनहरा पिंजरा है, जिसमें सांस तो आती है, पर आवाज़ नहीं। और अगर आप समलैंगिक हैं? तो आपका वजूद ही अपराध बन जाता है। यूएई में समलैंगिकता कानूनन अपराध है। सज़ा? जेल, जुर्माना, निर्वासन, और कुछ मामलों में मौत तक। अमेरिका में जहाँ धीरे-धीरे स्वीकार्यता बढ़ रही है, वहाँ से आकर यह देखना बेहद तकलीफदेह था कि कुछ लोग सिर्फ अपनी पहचान की वजह से सांस भी डरते-डरते लेते हैं।

इन सब बातों के बीच, विराट और अनुष्का का वो गले लगाना मुझे अब और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वो सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, वो शायद अनजाने में ही एक तरह की आज़ादी का इज़हार था। वो आज़ादी जो वहाँ के लाखों मज़दूरों को मयस्सर नहीं है। वो अपने बच्चों को वीडियो कॉल पर दुलार भी नहीं कर सकते, बिना डर के।

हम जैसे अमेरिका में बसे भारतीयों को अक्सर कहा जाता है कि हमने अपनी जड़ें छोड़ दीं, हम बहुत पश्चिमी हो गए हैं। लेकिन जब हम दुबई जैसे शहरों में जाते हैं और वहाँ अपने ही देश के लोगों को इस तरह की शर्तों में काम करते देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सवाल 'कहाँ रह रहे हैं' का नहीं है, सवाल यह है कि कैसे जी रहे हैं। दुबई चमकदार ज़रूर है, लेकिन उसकी रोशनी उन लोगों की आंखें चकाचौंध करती है जिनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम, जो कुछ ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, उन पर सिर्फ गर्व न करें जो क्रिकेट मैदान पर जीतते हैं, बल्कि उन पर भी ध्यान दें जो ज़िंदगी की कठोर ज़मीन पर हर पल जूझते हैं।

–डॉ. पंकज राजवंशी,
सिएटल (अमरीका) में एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं।

राशिफल

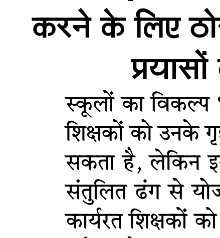

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 3 जुलाई, 2025

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 8:23 तक, परिघ योग सायं 6:35 तक, बव करण दिन 2:07 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:19 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज रवियोग दिन 1:50 से आरम्भ होगा। आज दुर्गाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:24 तक, चर 10:44 से 12:31 तक, लाभ-अमृत 12:31 से 3:56 तक, शुभ 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ और तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।